Steps to augment supply of ground water

2523. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the Central Govern ment contemplate to take steps to aug ment the supply of ground water in view of the successive drought; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE. OF THE MINISTRY OF TEXTILES AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) and (b) A number of measures like catchment treatment, water shed management and construction of percolation tanks are being undertaken to augment groundwater supplies.

Recovery of income tax from M/s. Beltk Electronics (P) Limited

2524. SHRI F. M. KHAN: Will the Minister of FINANCE be pleasea to state:

(a) what is theamount of income-tax due from M/s. Beltek Electronics (P) Limited, New Delhi for the last three years;

(b) what is the amount of income-tax paid during the same period; and

(c) what steps Government have taken to recover the arrears of income-tax?,

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): (a) NIL.

(b) Amount of income-tax paid by the company is as follows:—

Assessment *Years*	*Amount paid* (Rs. in *lakhs)*
1984-85	14.02
1985-86	25.32
1986-87	32.07

(c) In view of reply to (a) the Question of taking action does not arise.

Reopening of assessment cases of Bombay

2525. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Board of Direct Taxes has ordered for the reopening of all the cases assessed by Mr. K. K. Chaddha, Assistant Commissioner of Income Tax, Bombay, during the last 18 years of his stay in Bombay; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI); (a) No, Sir.

(b) In view of reply to (a) above, the question does not arise.

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में दिए गए ऋणों पर ब्याज लिया जाना

2526. श्री अजीत सिंह :
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में यह सुझाव दिया है कि बैंकों द्वारा बाढ़ तथा सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में दिए गए ऋणों पर चक्रवृद्धि ब्याज न लिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के हाल के परिपत्रों के अनुसार, बैंकों से सूखे और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में स्थगित देय राशियों के ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज में न बदलने और उन किसानों के मामलों में, जो 3 वर्ष या उससे अधिक समय से लगातार सूखे बाढ़ से पीड़ित हैं और जिनके ऋणों की परिवर्तित/पुनर्निर्धारित कर दिया गया है, 5000/- रुपए तक के अल्पावधिक ऋणों पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लेने के लिए कहा गया है । ब्याज की यह दर, वर्ष 1987–88 में इनमें से प्रत्येक वर्ष के वास्ते परिवर्तित/पुनर्निर्धारित अल्पावधिक ऋणों पर लागू होगी और इनका वास्तवी अदायगी आगामी वर्षों में देय किश्तों के अन्दर निर्धारित किश्तों के अनुसार की जाएगी ।

import of Horses

2527. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that horses imported for breeding purpose are given special exemption in the matter of basic duty charges; and

(b) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): (a) and (b) The statutory rate of basic customs duty leviable on imported horses is 100 per cent *ad valorem* (plus auxiliary duty of 45 per cent *ad valorem)*-A concessional rate of basic customs duty of 25 per cent *ad valorem* (plus auxiliary duty of 45 per cent ad *valorem)* is leviable on horses imported for purposes of breeding. The concession is in the interest of improving the breed of horses in the country

दिल्ली में ठेके के मजदूरों द्वारा खनन कार्य

2528. **श्री अजीत सिंह ,**

श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली में अभी तक भी खनन कार्य ठेकेदारी श्रम प्रणाली के अन्तर्गत किया जाता है ,

(ख) क्या यह भी सच है कि गत वर्ष के दौरान सरकार को इन ठेकेदारों के यहां बंधुआ मजदूरों के द्वारा काम किए जाने की शिकायतें कई बार प्राप्त हुई हैं, और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है और कितने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया है तथा उनके पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में खनन कार्य दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम के माध्यम से कराया जाता है जो सामान्यतः ठेका श्रम पद्धति को नहीं अपनाता है ।

(ख) जी, नहीं । न तो दिल्ली प्रशासन को और न ही दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Export of Synthetic and Blended Fabrics

2529. SHRI K. VASUDEVA PANICKER: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have forrajlated any long-term policy to boost exports of synthetic and blended fabrics: and